



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2010/भाद्र 22, 1932

No. 226]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2010/BHADRA 22, 1932

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

सं. एल/61/10/रा.वि.से.प्रा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 है ।

(2) ये भारत में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्ररूप” से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) “प्रबंध कार्यालय” से विधिक सेवा संस्था में वह कक्ष अभिप्रेत है, जहां विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ;

(घ) “विधि व्यवसायी” का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (झ) में है ;

(ङ) “विधिक सेवा संस्था” से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है ;

(च) “पैरा विधिक” स्वयंसेवक से विधिक सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित “पैरा विधिक” स्वयंसेवक अभिप्रेत है।

(छ) “सचिव” से विधिक सेवा संस्था का सचिव अभिप्रेत है।

(ज) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(झ) “राज्य विनियम” से अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है।

2. सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन—(1) विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में अधिमानतः प्ररूप-1 में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) कोई आवेदक अपनी शिकायत, जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता है, संक्षिप्त रूप में एक पृथक प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा।

(3) किसी आवेदन, यद्यपि प्ररूप-1 में नहीं है, को भी ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक ने विधिक सेवाएं चाहने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए तथ्यों को युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया है।

(4) यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है, विधिक सेवा संस्था आवेदक के आवेदन प्ररूप को भरने में और शिकायतों का एक टिप्पण तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था कर सकेगा।

(5) विधिक सेवा के लिए मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण किया जा सकेगा जिस रीति में कोई आवेदन उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है।

(6) पैरा विधिक स्वयं सेवकों, विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लीनिक्स और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जाएगा।

(7) आवेदक की पहचान का सत्यापन के पश्चात् और यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक/आवेदिका द्वारा की गई शिकायत उसकी स्वयं की है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए ई-मेल और ऑन-लाईन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध को भी विचार में लिया जा सकेगा।

4. विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना— (1) सभी विधिक सेवा संस्थाओं में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध पैनल वकील और एक या अधिक पैरा विधिक स्वयंसेवक के साथ प्रबंध कार्यालय होगा।

(2) न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं के मामले में, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अंग्रेषित करेगा और अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के लिए पैनल का वकील प्रबंध कार्यालय में ऐसी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(3) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील सूचनाओं का प्रारूपण, वकीलों की सूचनाओं का उत्तर भेजना और आवेदनों, अर्जियों आदि का प्रारूपण जैसी सेवाएं देगा।

(4) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारिवृंद से सचिवीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(5) अतिआवश्यक विषयों के मामले में, प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के सदस्य-सचिव या सचिव के परामर्श से समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा :

परंतु विनियम 7 के अधीन गठित की गई समिति प्रबंध कार्यालय में पैनल के वकील द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार और अनुमोदन कर सकेगी।

5. निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत— (1) आवेदक का एक शपथपत्र कि वह धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है प्रस्तुत करेगा जो कि साधारणतया पर्याप्त होगा।

(2) शपथ-पत्र को, यथास्थिति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद् सदस्य, विधान सभा सदस्य, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।

(3) शपथ-पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुद्रा होगी।

6. आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य बयानों का परिणाम—आवेदक द्वारा, यदि गलत या मिथ्या सूचना या कपटपूर्ण शैति द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त की गई है तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्था द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा।

7. निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन -- (1) तालुक, जिला, राज्य और उससे ऊपर के स्तर पर विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा संस्था द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी।

(2) समिति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

(i) अध्यक्ष के रूप में विधिक सेवा संस्था के सदस्य-सचिव या सचिव, और दो सदस्य जिसमें से एक न्यायिक अधिकारी हो सकेगा जिसे अधिमानतः विधिक सेवा संस्था में कार्य करने का अनुभव हो ;

(ii) यथास्थिति, एक विधिक वृत्तिक या सरकारी प्लीडर या सहायक सरकारी प्लीडर अथवा लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जिसे कम से कम 15 वर्ष का विधिज्ञ अनुभव हो ।

(3) समिति के सदस्यों की अवधि साधारणतया दो वर्ष की होगी जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा और विधिक सेवा संस्था का सदस्य-सचिव या सचिव, तथापि, समिति का पदेन अध्यक्ष बना रहेगा ।

(4) समिति आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करेगी तथा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यह विनिश्चय करेगी क्या आवेदक विधिक सेवाएं पाने का हकदार है या नहीं ।

(5) यदि, आवेदक धारा 12 में वर्णित प्रवर्ग के अधीन नहीं आता है, तो उसे स्वेच्छया या किसी अन्य स्कीम के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने वाले किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जाएगा ।

(6) विधिक सेवा संस्था ऐसे अभिकरणों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची रखेगा जिन्होंने निःशुल्क विधिक सेवाएं देने में अपनी रजामंदी व्यक्त की है ।

(7) समिति के विनिश्चय या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को अपील कर सकेगा या कर सकेगी और अपील पर किया गया विनिश्चय या आदेश अंतिम होगा ।

8. वकीलों के पैनल के रूप में विधि व्यवसायियों का चयन -- (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों के नाम पैनलित करने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे आवेदनों के साथ मामलों के प्रकार के विशेष संदर्भ के साथ वृत्तिक अनुभव का सबूत लगा होगा, जिसे आवेदक-विधि व्यवसायी को मामला सौंपे जाने में अधिमानता दी जा सकेगी ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महा अधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी अधिवक्ता (जिला और तालुक स्तर के लिए) और अपने-अपने बार संगम के अध्यक्षों से परामर्श करके वकीलों के पैनल का चयन किया जाएगा ।

(3) ऐसा विधि व्यवसायी, जिसके पास विधिज्ञ का तीन वर्ष से कम का अनुभव है, का नाम साधारणतया पैनलित नहीं किया जाएगा ।

(4) वकीलों का पैनल तैयार करने में ऐसे वकीलों की सक्षमता, निष्ठा, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा ।

(5) विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे सिविल, दांडिक, सांविधानिक विधि, पर्यावरण विधि, श्रमिक विधि, वैवाहिक विवाद आदि के लिए पृथक् पैनल रख सकेंगे ।

(6) विधिक सेवा संस्था का अध्यक्ष, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से पैनल वकीलों में से प्रतिधारक के रूप में किए जाने वाले विधि व्यवसायियों की एक सूची तैयार कर सकेगा ।

(7) प्रतिधारक वकीलों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा किया जाएगा ।

(8) प्रतिधारक वकीलों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :--

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में 20 ;

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में 15 ;

(ग) जिला विधिक प्राधिकरण में 10 ;

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति में 5 ।

(9) प्रतिधारक वकीलों को निम्नलिखित मानदेय संदेय होगा,-

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में 10,000/- रुपये प्रतिमास ;

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के दशा में 7,500/- रुपये प्रतिमास ;

(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दशा में 5,000/- रुपये प्रतिमास ;

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति के दशा में 3,000/- रुपये प्रतिमास ;

परंतु इस उपविनियम में विनिर्दिष्ट मानदेय विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में संदेय मानदेय या फीस के अतिरिक्त है ।

(10) प्रतिधारक के रूप में पदाविहित पैनल वकील अपना समय केवल विधिक सहायता कार्य के लिए लगाएंगे और विधिक सहायता मामलों से संबंधित के लिए क्रमशः विधिक सेवा संस्था के प्रबंध कार्यालय या परामर्श कार्यालय में सदैव उपलब्ध होंगे ।

(11) उपविनियम (2) के अधीन तैयार किया पैनल, तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनःगठित किया जाएगा किन्तु किसी पैनल वकील को पहले से ही सौंपे गए मामलों को पैनल के पुनःगठित होने के कारण उससे वापस नहीं लिया जाएगा ।

(12) विधिक सेवा संस्था कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान प्रतिधारक से कोई मामला वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगी ।

(13) यदि कोई पैनल वकील किसी मामले से हटना चाहता है तो वह सदस्य-सचिव या सचिव को कारणों का उल्लेख करेगा और उसके पश्चात् पैनल वकील को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(14) इन विनियमों के अधीन जिस व्यक्ति को विधिक सेवा दी जा रही हो, से पैनल वकील किसी भी शीति में कोई फीस, या पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल नहीं मांगेगा या प्राप्त करेगा ।

(15) यदि नियुक्त पैनल वकील संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या उसने अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कार्य किया है, तो विधिक सेवा संस्था समुचित कदम उठाएगी जिस के अंतर्गत ऐसे वकील से मामले से हटाना और उसे पैनल से हटाना भी सम्मिलित हैं ।

9. विधिक सलाह, परामर्श, प्रारूपण और हस्तांतर-लेखन के द्वारा विधिक सेवाएं -- (1) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष विधिक सलाह और अन्य विधिक सेवाएं जैसे प्रारूपण और हस्तांतर लेखन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ वकीलों, विधि फर्मों, सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों, मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और विधि विश्वविद्यालयों या विधि महाविद्यालयों में विधि प्राध्यापकों का एक पृथक पैनल रखेगा ।

(2) विधि सहायता क्लिनिक की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और विधि महाविद्यालयों तथा विधि विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रयोग में ली जाएगी ।

10. मानीटरी समिति -- (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था न्यायालय आधारित प्रदत्त विधिक सेवाओं और विधिक सहायता मामलों की प्रगति की निकट से मानीटरी के मामलों के लिए एक मानीटरी समिति की स्थापना करेगी ।

(2) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय स्तर पर, मानीटरी समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी--

(i) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ;

(ii) विधि सेवा संस्था का सदस्य सचिव या सचिव ;

(iii) विधिक सेवा संस्था के प्रमुख आश्रयदाता द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ज्येष्ठ अधिवक्ता ।

(3) जिला या तालुक विधिक सेवा संस्था के लिए मानीटरी समिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे,—

(i) संबंधित जिला में तैनात उच्च न्यायिक सेवा का ज्येष्ठतम सदस्य, इसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) विधिक सेवा संस्था का सदस्य-सचिव या सचिव ;

(iii) स्थानीय विधिज्ञ संगम के अध्यक्ष से परामर्श करके नामनिर्दिष्ट होने वाला विधि व्यवसायी जिसे स्थानीय विधिज्ञ संगम का पंद्रह वर्ष से अधिक का अनुभव हो :

परंतु यह कि यदि कार्यकारी अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि इस उप-विनियम में वर्णित किन्हीं प्रवर्गों का कोई व्यक्ति नहीं है तो वह ऐसे अन्य व्यक्तियों से मानीटरी समिति का गठन कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

11. मॉनीटरी समिति के कृत्य — (1) जब कभी किसी आवेदक को विधिक सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं, तो सदस्य-सचिव या सचिव यथाशीघ्र मॉनीटरी समिति को प्ररूप-2 में ब्यौरे भेजेगा।

(2) विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति के अभिलेख के रखने के लिए मॉनीटरी समिति को पर्याप्त कर्मचारिवृंद और अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

(3) विधिक सेवा संस्था न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मामलों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुरक्षित रजिस्ट्रों का अवलोकन करने के लिए निवेदन कर सकेगी।

(4) मॉनीटरी समिति उन मामलों की बाबत, जिनके लिए विधिक सहायता अनुज्ञात की गई है की दिन-प्रतिदिन की प्रविष्टियों, मामले की प्रगति और अंतिम परिणाम (सफलता या असफलता) का अभिलेख रखने के लिए, विधिक सहायता प्राप्त मामलों के लिए रजिस्टर रखेगी तथा उक्त रजिस्टर की संवीक्षा प्रत्येक मास समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(5) मॉनीटरी समिति, ऐसे समय के भीतर जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए, पैनल के वकीलों से रिपोर्ट भंगाकर न्यायालय की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाहियों पर निगरानी रखेगी।

(6) यदि मामले की प्रगति संतोषप्रद नहीं है तो समिति विधिक सेवा संस्था को समुचित कदम उठाने के लिए सलाह दे सकेगी।

12. मॉनीटरी समिति द्वारा द्वि-मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना — (1) मॉनीटरी समिति प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले की प्रगति और पैनल वकील या प्रतिधारक वकील के कार्य निष्पादन पर उसका स्वतंत्र मूल्यांकन अंतर्विष्ट करने वाली द्वि-मासिक रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

(2) समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात् विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष प्रत्येक मामले में की जाने वाली कार्यवाही विनिश्चित करेगा ।

(3) विधिक सेवा संस्था के सदस्य-सचिव या सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह मानीटरी समिति की रिपोर्ट विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे और आदेश प्राप्त करे ।

13. वित्तीय सहायता -- (1) यदि किसी मामले में, जिसके लिए विधिक सहायता अनुदत्त की गई है, अतिरिक्त व्यय जैसे न्यायालय फीस के संदाय, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन को संदेय फीस, साक्षियों या दस्तावेजों के समन के लिए, प्रमाणित प्रतियां आदि प्राप्त करने के लिए व्यय की अपेक्षा है तो विधिक सेवा संस्था पैनल के वकील या मॉनीटरी समिति की सलाह पर अपेक्षित रकम के संवितरण के लिए अतिआवश्यक उपाय करेगी ।

(2) अपील या पुनरीक्षण के मामले में, विधिक सेवा संस्था निर्णय और मामले के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए व्ययों का वहन कर सकेगी ।

14. पैनल के वकीलों को फीस का संदाय -- (1) पैनल के वकीलों को राज्य विनियमों के अधीन यथा अनुमोदित, फीस की अनुसूची के अनुसार फीस का संदाय किया जाएगा ।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता के मामलों में पैनल के वकीलों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए संदाय किए जाने वाले मानदेय का कालिक रूप से पुनरीक्षण करेंगे ।

(3) जैसे ही पैनल के वकील से कार्यवाही के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है, विधिक सेवा संस्था, बिना किसी विलंब के, पैनल के वकील को संदेय फीस और व्ययों का संदाय करेगी ।

15. समुचित मामलों में ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति-- (1) यदि मानीटरी समिति या विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष की यह राय है कि ज्येष्ठ वकील की सेवा, यद्यपि वह वकीलों के अनुमोदित पैनल में सम्मिलित नहीं है, किसी विशिष्ट मामले में प्रदत्त की जानी है, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे ज्येष्ठ वकील को नियुक्त कर सकेगी ।

(2) राज्य विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसे ज्येष्ठ वकील के लिए मानदेय का विनिश्चय कर सकेगा :

परंतु ज्येष्ठ वकीलों की विशेष नियुक्ति, केवल व्यापक लोक महत्त्व के मामलों और अत्यंत गंभीर प्रकृति के, आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले मामलों में बचाव के लिए ही की जाएगी ।

16. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता के मामलों का मूल्यांकन—(1) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की मॉनीटरी समिति की द्वि-मासिक रिपोर्टों की प्रतियां केन्द्रीय प्राधिकरण को भेजेगी ।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी मानीटरी समितियों की द्वि-मासिक रिपोर्टों की प्रतियां अपने प्रमुख आश्रयदाता को प्रस्तुत करेंगी ।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति अपनी मानीटरी समिति की द्विमासिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी ।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मानीटरी समिति की समेकित अर्धवार्षिक रिपोर्ट को, प्रत्येक विधिक सहायता प्राप्त मामले में सफलता या असफलता दर्शित करते हुए, केन्द्रीय प्राधिकरण को भेजेगा ।

(5) समुचित मामलों में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष इन विनियमों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा संस्था को पर्यवेक्षित करने, मॉनीटर करने या सलाह देने के लिए अपने केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों को नामनिर्देशित और प्राधिकृत कर सकेगा ।

यू. शरतचन्द्रन, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/123/10/असा.]

प्ररूप-1

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010

(विनियम-3 देखें)

विधिक सेवा के लिए आवेदन का प्ररूप
(इसे क्षेत्रीय भाषा में तैयार किया जाए)

- | | | |
|----|--|---|
| | रजिस्ट्रीकरण सं० | : |
| 1. | नाम | : |
| 2. | स्थायी पता | : |
| 3. | टेलीफोन सं० सहित, संपर्क का पता यदि कोई हो,
ई-मेल आईडी, यदि कोई हो | : |
| 4. | क्या आवेदक अधिनियम की धारा 12 में वर्णित व्यक्ति के
प्रवर्ग की श्रेणी में आता है | : |
| 5. | आवेदक की मासिक आय | : |
| 6. | क्या अधिनियम की धारा-12 के अधीन आय/अर्हता के
समर्थन में शपथपत्र/सबूत प्रस्तुत किया गया है | : |
| 7. | विधिक सहायता की प्रकृति या सलाह अपेक्षित है | : |
| 8. | मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक
सेवाएं अपेक्षित हैं ! | : |

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

प्रारूप-2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
(निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010
(विनियम-11 देखें)

प्रदत्त विधिक सेवा के बारे में मॉनीटरी समिति को दी गई सूचना

- (i) विधिक सेवा संस्था का नाम :
- (ii) विधिक सहायता आवेदन संख्यांक :
और वह तारीख जिसको विधिक सहायता दी गई ।
- (iii) विधिक सहायता आवेदक का नाम :
- (iv) मामले की प्रकृति (सिविल, दांडिक, संवैधानिक विधि आदि) :
- (v) आवेदक को समनुदेशित वकील का नाम और अनुक्रमांक :
- (vi) उस न्यायालय का नाम जिसमें :
मामला फाइल किया जाना है/प्रतिवाद किया जाना है ।
- (vii) पैनल के वकील को नियुक्त करने की तारीख :
- (viii) क्या अग्रिम के तौर पर कोई धनीय सहायता जैसे न्यायालय फीस, अधिवक्ता कमीशन फीस, प्रतिलिपि शुल्क आदि दी गई है ?
- (ix) क्या मामले में किसी अंतरिम आदेश या कमीशन की नियुक्ति की अपेक्षा है ?
- (x) अभिलेख प्रस्तुत करने, साक्षियों का समन करने आदि के लिए अनुमानित व्यय ।
- (xi) न्यायालय में कार्यवाही की समाप्ति के लिए अपेक्षित समय ।

सदस्य-सचिव/सचिव

तारीख :

**NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2010

No. L/61/10/NALSA.— *In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and in pursuance of the provisions in section 4 of the Act to make available free and competent legal services to the persons entitled thereto under section 12 of the said Act, the Central Authority hereby makes the following regulations, namely: -*

- 1. Short title, extent and commencement.** - (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010.
 - (2) They shall be applicable to Supreme Court Legal Services Committee, State Legal Services Authorities, High Court Legal Services Committees, District Legal Services Authorities and Taluk Legal Services Committees in India.
 - (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);
 - (b) “Form” means a Form annexed to these Regulations;
 - (c) “front office” means a room in the Legal Services Institution where legal services are made available;
 - (d) “legal practitioner” shall have the meaning assigned to it in clause (i) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
 - (e) “Legal Services Institution” means the Supreme Court Legal Services Committee, a State Legal Services Authority, the High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority or the Taluk Legal Services Committee, as the case may be;

- (f) "Para-Legal Volunteer" means a para-legal volunteer trained as such by a Legal Services Institution;
- (g) "Secretary" means the Secretary of the Legal Services Institution;
- (h) "section" means the section of the Act;
- (i) "State regulation" means regulation made by the State Authorities under the Act.

2. All other words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. **Application for legal services.-** (1) An application for legal services may be presented preferably in Form-I in the local language or English.

- (2) The applicant may furnish a summary of his grievances for which he seeks legal services, in a separate sheet along with the application.
- (3) An application, though not in Form-I, may also be entertained, if reasonably explains the facts to enable the applicant to seek legal services.
- (4) If the applicant is illiterate or unable to give the application on his or her own, the Legal Services Institutions may make arrangement for helping the applicant to fill up the application form and to prepare a note of his or her grievances.
- (5) Oral requests for legal services may also be entertained in the same manner as an application under sub-regulation (1) and (2).
- (6) An applicant advised by the para-legal volunteers, legal aid clubs, legal aid clinics and voluntary social service institutions shall also be considered for free legal services.
- (7) Requests received through e-mails and interactive on-line facility also may be considered for free legal services after verification of the identity of the applicant and on ensuring that he or she owns the authorship of the grievances projected.

- 4. Legal Services Institution to have a front office.-** (1) All Legal Services Institutions shall have a front office to be manned by a panel lawyer and one or more para-legal volunteers available during office hours.
- (2) In the case of court based legal services, such lawyer shall after consideration of the application, forward the same to the Committee set up under regulation 7 and for other types of legal services, the panel lawyer in the front office may provide such legal services.
- (3) The panel lawyer in the front office shall render services like drafting notices, sending replies to lawyers' notices and drafting applications, petitions etc.
- (4) The panel lawyer in the front office may obtain secretarial assistance from the staff of the Legal Services Institutions.
- (5) In case of urgent matters, the panel lawyer in the front office may in consultation with the Member-Secretary or Secretary of the Legal Services Institutions provide legal assistance of appropriate nature:
- Provided that the Committee set up under regulation 7 may consider and approve the action taken by the panel lawyer in the front office.
- 5. Proof of entitlement of free legal services. --** (1) An affidavit of the applicant that he falls under the categories of persons entitled to free legal services under section 12 shall ordinarily be sufficient.
- (2) The affidavit may be signed before a Judge, Magistrate, Notary Public, Advocate, Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, elected representative of local bodies, Gazetted Officer, teacher of any school or college of Central Government, State Government or local bodies as the case may be.
- (3) The affidavit may be prepared on plain paper and it shall bear the seal of the person attesting it.
- 6. Consequences of false or untrue details furnished by the applicant. -** The applicant shall be informed that if free legal services has been obtained by

furnishing incorrect or false information or in a fraudulent manner, the legal services shall be stopped forthwith and that the expenses incurred by the Legal Services Institutions shall be recoverable from him or her.

7. Scrutiny and evaluation of the application for free legal services. - (1)

There shall be a Committee to scrutinise and evaluate the application for legal services, to be constituted by the Legal Services Institution at the level of Taluk, District, State and above.

(2) The Committee shall be constituted by the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution and shall consist of, -

(i) the Member Secretary or Secretary of the Legal Services Institution as its Chairman and two members out of whom one may be a Judicial Officer preferably having working experience in the Legal Services Institution and;

(ii) a legal professional having at least fifteen years' standing at the Bar or Government pleader or Assistant Government Pleader or Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor, as the case may be.

(3) The tenure of the members of the Committee shall ordinarily be two years which may be further extended for a maximum period of one year and the Member Secretary or Secretary of the Legal Services Institution shall, however, continue as the ex-officio Chairman of the Committee.

(4) The Committee shall scrutinise and evaluate the application and decide whether the applicant is entitled to the legal services or not within a period of eight weeks from the date of receipt of the application.

(5) If the applicant is not covered under the categories mentioned in section 12, he or she shall be advised to seek assistance from any other body or person rendering free legal services either voluntarily or under any other scheme.

- (6) The Legal Services Institution shall maintain a list of such agencies, institutions or persons who have expressed willingness to render free legal services.
- (7) Any person aggrieved by the decision or order of the Committee, he or she may prefer appeal to the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution and the decision or order in appeal shall be final.

Selection of legal practitioners as panel lawyers. - (1) Every Legal Services Institution shall invite applications from legal practitioners for their empanelment as panel lawyers and such applications shall be accompanied with proof of the professional experience with special reference to the type of cases which the applicant-legal practitioners may prefer to be entrusted with.

- (2) The applications received under sub-regulation (1) shall be scrutinised and selection of the panel lawyers shall be made by the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution in consultation with the Attorney-General (for the Supreme Court), Advocate-General (for the High Court), District Attorney or Government Pleader (for the District and Taluk level) and the respective Presidents of the Bar Associations as the case may be.
- (3) No legal practitioner having less than three years' experience at the Bar shall ordinarily be empanelled.
- (4) While preparing the panel of lawyers the competence, integrity, suitability and experience of such lawyers shall be taken into account.
- (5) The Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution may maintain separate panels for dealing with different types of cases like, Civil, Criminal, Constitutional Law, Environmental Law, Labour Laws, Matrimonial disputes etc.
- (6) The Chairman of the Legal Services Institution may, in consultation with the Executive Chairman of the State Legal Services Authority or National Legal Services Authority as the case may be prepare a list of

legal practitioners from among the panel lawyers to be designated as Retainers.

- (7) The Retainer lawyers shall be selected for a period fixed by the Executive Chairman on rotation basis or by any other method specified by the Executive Chairman.
- (8) The strength of Retainer lawyers shall not exceed, -
 - (a) 20 in the Supreme Court Legal Services Committee;
 - (b) 15 in the High Court Legal Services Committee;
 - (c) 10 in the District Legal Authority;
 - (d) 5 in the Taluk Legal Services Committee.
- (9) The honorarium payable to Retainer lawyer shall be, -
 - (a) Rs.10,000 per month in the case of Supreme Court Legal Services Committee;
 - (b) Rs.7,500 per month in the case of High Court Legal Services Committee;
 - (c) Rs.5,000 per month in the case of District Legal Services Authority;
 - (d) Rs.3,000 per month in the case of the Taluk Legal Services Committee;

Provided that the honorarium specified in this sub-regulation is in addition to the honorarium or fee payable by the Legal Services Institution for each case entrusted to the Retainer lawyer.

- (10) The panel lawyers designated as Retainers shall devote their time exclusively for legal aid work and shall be always available to deal with legal aid cases and to man the front office or consultation office in the respective Legal Services Institution.
- (11) The panel prepared under sub-regulation (2) shall be re-constituted after a period of three years but the cases already entrusted to any panel lawyer shall not be withdrawn from him due to re-constitution of the panel.

- (12) The Legal Services Institution shall be at liberty for withdrawing any case from a Retainer during any stage of the proceedings.
- (13) If a panel lawyer is desirous of withdrawing from a case he shall state the reasons thereof to the Member-Secretary or the Secretary and the latter may permit the panel lawyer to do so.
- (14) The panel lawyer shall not ask for or receive any fee, remuneration or any valuable consideration in any manner, from the person to whom he had rendered legal services under these regulations.
- (15) If the panel lawyer engaged is not performing satisfactorily or has acted contrary to the object and spirit of the Act and these regulations, the Legal Services Institution shall take appropriate steps including withdrawal of the case from such lawyer and his removal from the panel.

9. Legal services by way of legal advice, consultation, drafting and conveyancing. - (1) The Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution shall maintain a separate panel of senior lawyers, law firms, retired judicial officers, mediators, conciliators and law professors in the law universities or law colleges for providing legal advice and other legal services like drafting and conveyancing.

(2) The services of the legal aid clinics in the rural areas and in the law colleges and law universities shall also be made use of.

10. Monitoring Committee. - (1) Every Legal Services Institution shall set up a Monitoring Committee for close monitoring of the court based legal services rendered and the progress of the cases in legal aided matters.

(2) The Monitoring Committee at the level of the Supreme Court or the High Court, as the case may be, shall consist of, -

- (i) the Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee or Chairman of the High Court Legal Services Committee;
- (ii) the Member-Secretary or Secretary of the Legal Services Institution;

- (iii) a Senior Advocate to be nominated by the Patron-in-Chief of the Legal Services Institution.
- (3) The Monitoring Committee for the District or Taluk Legal Services Institution shall be constituted by the Executive Chairman of the State Legal Services Authority and shall consist of, -
 - (i) the senior-most member of the Higher Judicial Services posted in the district concerned, as its Chairman;
 - (ii) the Member-Secretary or Secretary of the Legal Services Institution;
 - (iii) a legal practitioner having more than fifteen years' experience at the local Bar-to be nominated in consultation with the President of the local Bar Association:

Provided that if the Executive Chairman is satisfied that there is no person of any of the categories mentioned in this sub-regulation, he may constitute the Monitoring Committee with such other persons as he may deem proper.

- 11. Functions of the Monitoring Committee.** - (1) Whenever legal services are provided to an applicant, the Member-Secretary or Secretary shall send the details in Form-II to the Monitoring Committee at the earliest.
- (2) The Legal Services Institution shall provide adequate staff and infrastructure to the Monitoring Committee for maintaining the records of the day-to-day progress of the legal aided cases.
 - (3) The Legal Services Institution may request the Presiding Officer of the court to have access to the registers maintained by the court for ascertaining the progress of the cases.
 - (4) The Monitoring Committee shall maintain a register for legal aided cases for recording the day-to-day postings, progress of the case and the end result (success or failure) in respect of cases for which legal aid is allowed and the said register shall be scrutinised by the Chairman of the Committee every month.

- (5) The Monitoring Committee shall keep a watch of the day-to-day proceedings of the court by calling for reports from the panel lawyers, within such time as may be determined by the Committee.
- (6) If the progress of the case is not satisfactory, the Committee may advise the Legal Services Institution to take appropriate steps.

12. Monitoring Committee to submit bi-monthly reports. – (1) The Monitoring Committee shall submit bi-monthly reports containing its independent assessment on the progress of each and every legal aid case and the performance of the panel lawyer or Retainer lawyer, to the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution.

- (2) After evaluating the reports by the Committee, the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution shall decide the course of action to be taken in each case.
- (3) It shall be the duty of the Member-Secretary or Secretary of the Legal Services Institution to place the reports of the Monitoring Committee before the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution and to obtain orders.

13. Financial assistance. – (1) If a case for which legal aid has been granted requires additional expenditure like payment of court fee, the fee payable to the court appointed commissions, for summoning witnesses or documents, expenses for obtaining certified copies etc., the Legal Services Institution may take urgent steps for disbursement of the requisite amount on the advice of the panel lawyer or Monitoring Committee.

- (2) In the case of appeal or revision the Legal Services Institution may bear the expenses for obtaining certified copies of the judgment and case records.

14. Payment of fee to the panel lawyers. - (1) Panel lawyers shall be paid fee in accordance with the Schedule of fee, as approved under the State regulations.

- (2) The State Legal Services Authority and other Legal Services Institution shall effect periodic revision of the honorarium to be paid to panel lawyers for the different types of services rendered by them in legal aid cases.
- (3) As soon as the report of completion of the proceedings is received from the panel lawyer, the Legal Services Institution shall, without any delay, pay the fees and expenses payable to panel lawyer.

15. Special engagement of senior advocates in appropriate cases. – (1) If the Monitoring Committee or Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution is of the opinion that services of senior advocate, though not included in the approved panel of lawyers, has to be provided in any particular case the Legal Services Institution may engage such senior advocate.

- (2) Notwithstanding anything contained in the State regulations, the Executive Chairman or Chairmen of the Legal Services Institution may decide the honorarium for such senior advocate:

Provided that special engagement of senior advocates shall be only in cases of great public importance and for defending cases of very serious nature, affecting the life and liberty of the applicant.

16. Evaluation of the legal aid cases by the National Legal Services Authority and State Legal Services Authorities. – (1) The Supreme Court Legal Services Committee shall send copies of the bi-monthly reports of the Monitoring Committee of the Supreme Court Legal Services Committee to the Central Authority.

- (2) The High Court Legal Services Committees, the State Legal Services Authorities shall submit copies of the bi-monthly reports of their Monitoring Committees to their Patron-in-Chief.
- (3) The District Legal Services Authorities and Taluk Legal Services Committees shall submit copies of the bi-monthly reports of their Monitoring Committees to the Executive Chairman of the State Legal Services Authority.

- (4) The State Legal Services Authorities shall also send consolidated half-yearly reports of the Monitoring Committees, indicating the success or failure of each of the legal aided cases, to the Central Authority.
- (5) In appropriate cases, the Executive Chairman of the National Legal Services Authority may nominate and authorise the members of its Central Authority to supervise, monitor or advise the Legal Services Institution for effective and successful implementation of these regulations.

U. SARATHCHANDRAN, Member-Secy.

[ADVT. III/4/123/10/Exty.]

Form -I

**National Legal Services Authority
(Free and Competent Legal Services) Regulations, -2010**

(see regulation-3)

The Form of Application for Legal Services

(this may be prepared in the regional language)

- Registration No. :
1. Name :
2. Permanent Address :
3. Contact Address with phone no. if any,
e-mail ID, if any. :
4. Whether the applicant belongs to the category
of persons mentioned in section -12 of the Act :
5. Monthly income of the applicant :

6. Whether affidavit/proof has been produced
in support of income/eligibility u/s 12 of the Act :
7. Nature of legal aid or advise required :
8. A brief statement of the case, if court based
legal services is required. :

Place:

Date:

Signature of the applicant

Form-II

**National Legal Services Authority
(Free and Competent Legal Services) Regulation, 2010**

(see regulation-11)

Information furnished to the Monitoring Committee about the legal Services provided

- (i) Name of the Legal Services Institution. :
- (i) Legal aid application number and date on which legal aid was given. :
- (iii) Name of the legal aid applicant. :
- (iv) Nature of case (civil, criminal, constitutional law etc.). :
- (v) Name and roll number of the lawyer assigned to the applicant. :
- (vi) Name of the Court in which the case is to be filed / defended. :

- (vii) The date of engaging the panel lawyer. :
- (viii) Whether any monetary assistance like, :
court fee, advocate commission fee, copying
charges etc. has been given in advance?
- (ix) Whether the case requires any interim orders :
or appointment of commission?
- (x) Approximate expenditure for producing :
records, summoning of witnesses etc.
- (xi) The expected time for conclusion of the :
proceedings in the Court.

MEMBER-SECRETARY / SECRETARY

Dated: